



ISSN Print: 2394-7500  
 ISSN Online: 2394-5869  
 Impact Factor: 5.2  
 IJAR 2015; 1(8): 570-571  
 www.allresearchjournal.com  
 Received: 08-05-2015  
 Accepted: 09-06-2015

**Rakesh Kumar Sharma**  
 Research Scholar, Business  
 school, Faculty of commerce  
 and Business Management  
 Studies, Himachal Pradesh  
 University Shimla-5

## हिमाचल प्रदेश: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उभरते आयाम

**Rakesh Kumar Sharma**

हिमाचल प्रदेश एक विस्तृत पहाड़ी राज्य है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे जुड़े क्षेत्रों का लगभग 20% योगदान है। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक प्रान्त है। इसकी सीमायें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ तिब्बत के साथ भी लगती हैं। हिमाचल प्रदेश में देवी-देवताओं का स्थान होने के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की आबादी लगभग 70 लाख है। आजादी के 67 वर्षों के उपरांत हिमाचल प्रदेश ने विकास की नई ऊँचाइयों को छुआ है। हिमाचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, स्वावलंबन, स्वरोजगार और सपन्नता अन्य राज्यों से अधिक वेहतर हैं। हिमाचल प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ अभी भी विकास के मार्ग में बाधा हैं, जिन्हें आने वाले समय में नियन्त्रण में लाना पड़ेगा। सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग तथा प्रदेश के विकास की जीवन रेखाएँ हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने हिमाचल प्रदेश के गाँवों को सड़कों से जोड़कर एक नया अध्याय लिखा है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित देने के लिए नए शिक्षा संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण समाज की अपनी अनूठी पहचान है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सांस्कृतिक परम्पराओं की धरोहर को संजोकर रखा जा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लोक गीत, लोकनृत्य आज भी समाज को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के लोगों ने सैनिक व सांस्कृतिक प्रहारों को झेलने के बाद भी संघर्ष करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक मूल्यों को वचाए रखा। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्योग एवं जलविद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है।

कृषि एवं बागवानी: हिमाचल प्रदेश में कृषि एवं बागवानी अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा हैं। प्रदेश में 70% लोगों की आय कृषि एवं बागवानी पर निर्भर है। राज्य में कृषि योग्य भूमि 10<sup>पू४</sup> प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में 80:भूमि वर्षा द्वारा सिंचित है और किसान इंद्र देवता की कृपा पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को व्यापक रूप से कृषि बागवानी के अनुकूल जलवायु और परिस्थितियाँ दी हैं जिसके कारण प्रदेश में विविध फल एवं सब्जियाँ उगाने में मदद मिलती है। प्रदेश में फलों एवं सब्जियों के विपणन हेतु 52 मंडियाँ कार्यरत हैं। जिनमें लगभग 4 लाख टन फलों एवं सब्जियों का कारोवार हो रहा है। बागवानी के विकास में हिमाचल प्रदेश ने देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। राज्य में 2<sup>पू१५</sup> लाख हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अधीन हैं और फल उत्पादन 8<sup>पू१८</sup> लाख मीट्रिक टन हो गया है। बागवानी क्षेत्र से राज्य की वार्षिक आय में लगभग 4098 करोड़ रुपय का योगदान है तथा लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश का सेव पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है वहीं चुनौतियों भी कम नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। वरसात के दिनों में संपर्क टूट जाने से ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी एवं फलों को मंडी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। वैश्विक चुनौतियों तथा बदलते मौसम के अनुसार उन्नत

Correspondence:  
**Rakesh Kumar Sharma**  
 Research Scholar, Business  
 school, Faculty of commerce  
 and Business Management  
 Studies, Himachal Pradesh  
 University Shimla-5

किस्म के बीजों और पोथों की आवश्यकता भी किसानों एवं बागवानों के लिए जरूरी है।

पर्यटन: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के विस्तार से जहाँ एक ओर युवाओं को रोजगार मिल रहा वहीं दूसरी ओर प्रदेश की आय में भी वृद्धि हो रही है। शिमला, मनाली, रोहतांग, धर्मशाला, डलहौजी तथा खजियार मुख्य पर्यटक स्थल हैं। हर वर्ष पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छी सड़कें, पार्किंग व्यवस्था तथा अच्छे होटल पर्यटन को बढ़ावा देने में मूलभूत तंत्र हैं। राज्य को वर्षभर पर्यटकों के आकर्षण केंद्र बनाने तथा पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाने की आवश्यकता है। राज्य के सतत पर्यटन विकास के लिए संसोधित पर्यटन नीति तैयार करने की जरूरत है।

जल-विधुत: जलविधुत एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने की क्षमता है। प्रदेश में 27436 मैगावाट जल-विधुत क्षमता है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जल-विधुत परियोजनाओं से लगभग 9000 मैगावाट विजली ही पैदा की जाती है। सरकारी, संयुक्त तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में उपलब्ध जल-विधुत का दोहन किया जा सकता है। अधिक जलविधुत के उत्पादन से प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। उद्योगों के विकास से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

ग्रामीण विकास विभाग: ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हमारी योजना प्रक्रिया का प्राथमिक विषय है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण तथा शहरी विभाजन को पाटना, गरीबी हटाना, रोजगार सृजन, मूल संरचना विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी० आर० डी० ए०) के माध्यम से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि योजनाओं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ठीक तरह से किया जा सके।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा की योजना ने जहाँ एक तरफ रोजगार को बढ़ावा दिया वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में नए आयाम स्थापित किये हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी० आर० डी० ए०) गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सभी जिलों में विशेष भूमिका निभा रहा है। डी० आर० डी० ए० जिलों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजित करने वाली सभी संस्थाओं के बीच समन्वय बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और तेजी की वजह से योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, और विकलांगों तक पहुँच रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के विकास के लिए चलाये जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विकास खंड एक महत्वपूर्ण इकाई है।

हिमाचल प्रदेश में मनरेगा की योजना शुरू होने के बाद ग्रामीण विकास की गति तेज हुई तथा इस कार्य में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ी है। हमीरपुर, मंडी तथा किन्नौर जिलों में मनरेगा के कार्यों में महिलाओं की सहभागिता 60: के आसपास है। महिलाओं की सहभागिता से वच्चों की शिक्षा पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा है। मनरेगा कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके चलाने

में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रीय भूमिका के चलते ग्रामीण प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो रहा है और इस तरह लोकतंत्र तथा पारदर्शिता की जड़ें मजबूत हो रही हैं। मनरेगा की योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों का निर्माण, परम्परागत जल संसाधनों का नवीनीकरण, कृषि एवं बागवानी के कार्यों को गति मिली है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशेड योजना के क्रियान्वयन के बाद जहाँ एक तरफ सिंचाई की व्यवस्था में सुधार हुआ वहीं दूसरी तरफ जलस्तर में भी सुधार हो रहा है। शुरू में वाटरशेड योजना के परिणाम अच्छे नहीं थे लेकिन धीरे-धीरे जनसहभागिता के कारण अच्छे परिणाम आ रहे हैं। वाटरशेड परियोजना हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण तथा भूमि-कटाव को रोकने में सक्षम भूमिका निभा रही है।

गुणात्मक शिक्षा तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत में 20वें स्थान पर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वें स्थान पर है। प्रतिव्यक्ति की आय की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष में चौथे स्थान पर पहुँच गया है जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने जो गति पकड़ी है उसे आने वाले समय में नई ऊँचाइयों तक जाना है। समाज के सभी वर्गों का विकास तथा प्रदेश के सभी क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास हो ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण करके ही हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। कृषि एवं बागवानी, पर्यटन तथा जलविधुत को योजनाओं के विस्तार से जहाँ एकतरफ हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा वहीं दूसरी तरफ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलम्बी बनाया जा रहा है। खादी प्रामोदोग की ओर से करीब सौ से ज्यादा कारोवार ऐसे चलाये जा रहे हैं जो पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे कारोवारों को शुरू करने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है और युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता है। इस तरह के कारोवार शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन थमा है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में भी सुधार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित कर गाँवों में तैयार होने वाले उत्पादों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि, बागवानी, पर्यटन, ग्रामोद्योग तथा जलविधुत की योजनाएँ हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सुधार में हर दिन नए आयाम स्थापित कर रही हैं।

#### References:

1. Kurukshetra. A Journal on Rural Development May, 2014, 62(7).
2. Annual Administrative Report Department of Rural development, Himachal Pradesh, 2014-15.
3. State Institute of Rural development (SIRD), Research Highlights, 2013-14.
4. Annual Report of University of Forestry and Horticulture Solan Himachal Pradesh.